प्रेषक,

आरव्डीव्पालीवाल, सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।

संवा में.

महानिबन्धक

मो॰ उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,

नैनीताल ।

न्याय अनुधाग : 2

देहरादून : दिनांक : 1% मार्च, 2008

विषय: सिविल न्यायालय परिसर, हल्द्वानी में श्रेणी-।। के 20 आवासों के निर्माण हेतु विलोय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वोक्ति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1121/यूएचसी/एडमिन.बी/निर्माण/2006, दिनांक 2.4.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

- 2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल न्यायालय परिसर, हल्द्वानी में श्रेणी-11 के 20 आवासों के निर्माण हेतु रू० 94,48,000/- के आगणन के सापेक्ष टी॰ए॰सी॰ द्वारा अनुमोदित रू० 75,12,000/- (पचहत्तर लाख बरह हजार रूपये मात्र) को लागन के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू० 75,12,000/- (पचहत्तर लाख बारह हजार रूपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वोकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहयं प्रदान करते हैं :-
  - (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधोक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीक्त/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
  - (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त को जाय तथा उच्च अधिकारियों के निरोक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
  - (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।
  - (4) एक पुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमादन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।
  - (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनोको दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप हो कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
  - (6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भलो-भांति निरोक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरोक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।
  - (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि इसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
  - (8) निर्माण सत्मग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, विलीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के 191 सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विपयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अधियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

पुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), (10) दिनाक 30.5.2006 द्वारा निर्मत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

स्वोकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वोकृत धनराशि (11) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान विल्लीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यो हेतु भवनो का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यं" के नामें डाला जायंगा ।

4. यह आदेश विल अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1495/XXVII(5)/2008,दिनांक 17.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

( आर०डी॰पालीवाल ) सचिव 1

## संख्या- 68-रो(8)/XXXV1(1)(2)/2007-08-107-रो(1)/05-तर्दिनांकः । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून । 1.
- मुख्य सचिव, उताराखण्ड शासन, देहरादून । 2.
- जिला न्यायाधीश, नैनोताल । 3.
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-१ लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
- अधिशासी अधियन्ता, निर्माण खण्ड, त्योक निर्माण विभाग, हल्द्वानी । 6.
- नियोजन विभाग/विता अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन । 7.
- ्र एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

( आलोक र्नुमार वर्मा ) अपर सचिव ।